हिन्दी सान्ध्य दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 02 अंक : 39 : जौनपुर, गुरुवार 02 नवम्बर 2023 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज – 4 मूल्य : 2 रूपया

पड़ोसी देशों के साथ भी सबका साथ, सबका विकास चाहता है भारत : मोदी

एजेन्सी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं और नयी दिल्ली ने ढाका के साथ भी श्सबका साथ, विकासश का दृष्टिकोण अपनाया है। पीएम मोदी ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ भारतीय सहायता से निर्मित तीन परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कहा, ष्हमने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए भी सबका साथ, सबका विकास का दृष्टिकोण अपनाया है। हमें बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा विकास भागीदार होने पर गर्व है। पिछले नौ वर्षों में, 10 बिलियन डॉलर की सहायता दी गई है। उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है।ये परियोजनाएं हैं अखौरा–अगरतला क्रॉस–बॉर्डर रेल

लिंकय खुलना–मोंगला पोर्ट रेल लाइनय और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट–प्...मोदी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में हमारा आंतरिक व्यापार तीन गुना हो गया है।आज अखौरा–अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन एक ऐतिहासिक क्षण है। यह बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच पहला रेल लिंक है। मुक्ति संग्राम के दिनों से ही त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ मजबूत संबंध रहा है, मुझे खुशी है कि हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट की दूसरी यूनिट का उद्घाटन किया है।सीमा पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता स्थापित करने के लिए, हमने भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दशकों से लंबित था। हमने समुद्री सीमा का भी समाधान किया... पिछले नौ वर्षों में, ढाका को शिलांग, अगरतला, गुवाहाटी और कोलकाता से जोड़ने वाली तीन नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। पिछले नौ वर्षों में तीन नई ट्रेन सेवाएं भी शुरू हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ष्2020 से भारत और बांग्लादेश के बीच पार्सल और कंटेनर ट्रेनें भी चल रही हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास शुरू करने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। मोदी ने आगे कहा कि यह खुशी की बात है कि एक बार फिर हम भारत–बांग्लादेश सहयोग की सफलता का जश्न मनाने के लिए जुड़े हैं। हमारे रिश्ते लगातार नई ऊंचाईयां छू रहे हैं। पिछले 9 सालों में हमने मिलकर जो काम किया है, वह इससे पहले के दशकों में भी नहीं हुआ था। अपनी ओर से, हसीना ने ष्दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। बांग्लादेश की नेता ने दोनों देशों द्वारा बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान पर बनी बायोपिक की स्क्रीनिंग की भी सराहना की। हसीना ने कहा, मैं पीएम मोदी के प्रति अपनी गहरी सराहना और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगी। (शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन की) स्क्रीनिंग अब बांग्लादेश और भारत दोनों में चल रही है।

अक्टूबर में यूपी को मिली 9078.05 करोड़ की सौगात

एजेन्सी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेहरबान हैं। वहां भी विकास की बयार बह रही है। जहां मिशन शक्ति से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन पर ध्यान दिया तो वहीं अनेक जिलों में पहुंचकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा। जनपदों में मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास की जमीनी हकीकत से रूबरू होने वाला रहा। सभी जनपदों में समान रूप से विकास की गंगा बहाने वाले सीएम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियो व आमजन से विकास की बातें कीं और मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा।

सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यूपी के 80 जनपदों में समान रूप से विकास कार्य होते हैं। वे स्वयं जनपदों में जाकर जमीनी हकीकत परखने में विश्वास करते हैं। अक्टूबर में सीएम दो दर्जन से अधिक जनपदों का दौरा किया और 9078.05 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को गति दिया। 4484 कार्यों

का शिलान्यास–लोकार्पण कर सड़क, पेयजल, स्वच्छता, पुल आदि मूलभूत सुविधाओं को आगे बढ़ाया।सीएम योगी व्यस्तता व कार्यक्रमों के बीच भी युवाओं का ध्यान रखना न भूले। लखनऊ में 10 अक्टूबर को 394 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट ,3 अक्टूबर को यूपी लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्य को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले के तहत स्वरोजगार के लिए 500 करोड़ का ऋण किया वितरित, कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर सुखद भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। शारदीय नवरात्रि के पहले जहां मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण का आगाज किया। कई नियुक्ति पत्र व योजनाओं की लाभार्थियों को चाबी, टैबलेट आदि देकर उन्हें स्वावलंबन से भी जोड़ा। रामनगरी में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया और यहीं से महिलाओं को रोडवेज बसों में सारथी चालक के रूप में स्थापित होने में कारगर भूमिका भी निभाई। योगी सरकार के प्रयास से शक्ति की प्रतीक बेटियां इन गाड़ियों को चलाते भी दिखीं।

यूपी के पूर्व जदयू सांसद धनंजय सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज

एजेन्सी

जौनपुर। जनता दल (यूनाइटेड) (जद–यू) के राष्ट्रीय महासचिव एवं बाहुबली नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके 12 समर्थकों के खिलाफ गलत तरीके से भीड़ जुटाने और ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप में सदर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) कुलदीप गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर बाहुबली नेता एवं पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज के मैदान से कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा तक 'जन एकताश रैली निकाली थी। रैली में बहुत भीड़ इकठ्ठा की गई थी। साथ ही, लाउड स्पीकर का अवांछित प्रयोग किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में शकर मण्डी चौकी प्रभारी कंचन पाण्डेय की शिकायत पर धनंजय सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ मंगलवार रात मामला दर्ज किया गया।

बीसीसीआई ने दिल्ली, मुंबई मैच में पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी

एजेन्सी

नयी दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) ने दिल्ली और मुंबई में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को देखते हुए इन दोनों शहरों में विश्व कप के शेष मैचों के दौरान आतिशबाजी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुंबई 2 नवंबर (भारत बनाम श्रीलंका), 7 नवंबर (ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान) और 15 नवंबर को सेमीफाइनल की मेजबानी करेगा, जबकि दिल्ली बांग्लादेश और श्रीलंका

के बीच अपने आखिरी लीग मैच की मेजबानी 6 नवंबर को करेगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बुधवार को एक मीडिया बयान में कहा, श्श्बीसीसीआई पर्यावरण संबंधी चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। मैंने इस मामले को औपचारिक रूप से आईसीसी के सामने उठाया और मुंबई में कोई आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं होगा, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। बोर्ड पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने प्रशंसकों और हितधारकों के हितों को हमेशा सबसे आगे रखेगा।"

बीसीसीआई मुंबई और नयी दिल्ली दोनों में वायु गुणवत्ता को लेकर तत्काल चिंता को स्वीकार करता है जबकि हम क्रिकेट के उत्सव के अनुरूप आईसीसी विश्व कप की मेजबानी करने का प्रयास करते हैं, हम अपने सभी हितधारकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। उपर्युक्त दोनों शहर हवा की बहुत खराब गुणवत्ता का सामना कर रहे हैं, दिल्ली में बुधवार को 372 के एक्यूआई के साथ ष्बहुत खराबष् दर्ज किया गया, जबकि मुंबई 150–200 के एक्यूआई के साथ खराब श्रेणी में था।

उत्तराखंड में निकाय चुनाव में हो रही देरी पर बीजेपी–कांग्रेस आमने सामने

एजेन्सी

देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव होना है, लेकिन अभी तक तारीख तय नहीं हो पाई है। निकाय चुनाव में हो रही देरी के लिए अब दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। निकाय चुनाव में हो रही देरी के लिए जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से पूछा गया तो उन्होंने निकाय चुनावो के समय पर ना होने के सवाल पर उलटा विपक्षी कांग्रेस को ही सवालों के घेरे मे खड़ा कर दिया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पहले ये बताए कि प्रदेश मे उनकी दो बार सरकार रही है। उन्होंने कब निकाय चुनाव समय पर कराए। उनके अनुसार प्रदेश मे कई नए निकाय बने हैं। ऐसे मे सभी में आरक्षण सहित तमाम प्रक्रिया जारी है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, चुनाव करा दिए जायेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को निकाय चुनाव समय पर ना होने पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। क्योंकि उन्होंने खुद समय पर चुनाव नहीं कराए हैं। वहीं सदन में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष को ये बात नहीं कहनी चाहिए। उनके अनुसार कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं, इसे कहने की जगह वो ये बताएं कि आपने क्या किया।

टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू अंतरिम जमानत के बाद घर लौटे तो भावनात्मक हुआ माहौल

एजेन्सी

अमरावती। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू राजमुंदरी जेल से बाहर आने के 13 घंटे बाद बुधवार सुबह जब अपने आवास पर पहुंचे, तो भावनात्मक दृश्य देखने को मिला।

परिवार के सदस्यों और समर्थकों के गर्मजोशी से स्वागत के लिए पहुंचे नायडू उस समय भावुक हो गए, जब उनके कुछ रिश्तेदार उन्हें गले लगाते समय रोने लगे।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख ने उन्हें सांत्वना दी और साहस रखने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ पूजा में भाग लिया। नायडू सुबह 5 बजे के बाद उंदावल्ली स्थित अपने आवास पहुंचे। उनकी पत्नी भुवनेश्वरी ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। पुजारियों ने विभिन्न अनुष्ठान किए। बड़ी संख्या में टीडीपी की महिला नेता और कार्यकर्ता हाथों में गुम्मदिकाया (कद्दू) लेकर कतार में खड़ी थीं। उन्होंने कद्दू तोड़े, यह कार्य शुभ माना जाता है। कौशल विकास निगम मामले में 52 दिन न्यायिक हिरासत में बिताने के बाद, स्वास्थ्य आधार पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के बाद नायडू मंगलवार को जेल से बाहर आए थे।

नायडू शाम करीब 4.40 बजे राजमुंदरी सेंट्रल जेल से बाहर निकले थे। उनके परिवार के सदस्यों, टीडीपी नेताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। लोगों और विभिन्न राजनीतिक दलों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देने के बाद, वह वाहनों के एक विशाल काफिले में अमरावती के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए। पूरे रास्ते में हजारों समर्थकों ने 73 वर्षीय नायडू का गर्मजोशी से स्वागत किया। जगह–जगह उनके स्वागत के लिए स्त्री–पुरुष कतार में खड़े थे। वे पुष्पवर्षा कर रहे थे और जय बाबू जय–जय बाबू के नारे लगा रहे थे। आधी रात के बाद भी उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उमड़ पड़े। भारी भीड़ के कारण मार्ग में कई स्थानों पर यातायात जाम हो गया।

तीन तारीख को फिर बनेगी भाजपा सरकार, उसके बाद मनाएंगे राज्य का स्थापना दिवसः शिवराज

एजेन्सी

भोपाल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य के स्थापना दिवस पर कहा कि अभी आदर्श आचार संहिता के कारण स्थापना दिवस समारोह आयोजित नहीं किया जा सकता, लेकिन आगामी तीन दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद धूमधाम से राज्य का स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। चौहान ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि हर साल आनंद और उत्साह से राज्य का स्थापना दिवस समारोह मनाने की परंपरा भाजपा सरकार ने शुरु की, लेकिन इस बार आचार संहिता के कारण स्थापना दिवस का शासकीय तौर पर आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि तीन दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और फिर तिथि निश्चित कर धूमधाम से स्थापना दिवस समारोह मनाएंगे। उन्होंने कहा कि समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश का आगे का रोडमैप तैयार कर उस पर चलने का संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा कि 68 वर्ष में प्रदेश ने प्रगति की लंबी मंजिल तय की है। 2003 में भाजपा ने शासन संभाला था, तब की स्थितियों के बाद से राज्य में आमूलचूल परिवर्तन आया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। शहरों में प्रगति और विकास के साथ स्वच्छता में भी प्रदेश नंबर एक पर है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी प्रदेश में लगातार हो रहा है।

महाकाल लोक, एकात्म धाम, हनुमान लोग, देवी लोक जैसे बहुत से स्मारक बनाए हैं। प्रदेश तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राज्य के 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जानते हैं कि एक समय में मध्यप्रदेश को बीमारू कहा जाता था, पर आज हम समृद्ध और विकसित राज्यों की पांत में खड़े हैं। राज्य को अभी आगे की ओर ले जाना है।

भाजपा केवल 'पुलिस, पैसे और प्रशासन' के सहारे : कमलनाथ

एजेन्सी

नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर पुलिस, पैसे और प्रशासन के दम पर सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जनता इस कुशासन से मुक्ति चाहती है। श्री कमलनाथ ने नरसिंहपुर के करेली में आयोजित कांग्रेस की चुनावी सभा में कहा कि स्कूली बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप देने का काम कांग्रेस की सरकार करने वाली है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब वोट देने जायें तो कांग्रेस के वचनपत्र को पढ़कर जायें। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य, पंचायत व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सब चौपट हैं और रोजगार भी नहीं है। प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार से पीड़ित है। श्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि सरकार ने मध्यप्रदेश के भविष्य पर ताला लगा रखा है।

विपक्षी नेताओं की फोन निगरानी पर महुआ मोइत्रा ने ओम बिड़ला को लिखा पत्र

एजेन्सी

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर विपक्षी सदस्यों पर राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा दूरस्थ निगरानी के तत्काल खतरे में हस्तक्षेप करने की मांग की। मोइत्रा के 1 नवंबर को लिखे पत्र में कहा,ष्यह बहुत निराशा के साथ है कि मैं आपको एक संदेश के बारे में सूचित करने के लिए लिख रहा हूं कि मुझे और लोकसभा के कई अन्य सदस्यों (सभी विपक्षी दलों से संबंधित) को हमारे मोबाइल पर ऐप्पल से एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि हमें श्निशाना बनाया जा रहा हैश राज्य–प्रायोजित हमलावर हमारे उपकरणों से दूर से छेड़छाड़ करने और हमारे डेटा, संचार और यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पेगासस सॉफ्टवेयर के मद्देनजर यह खतरा चौंकाने वाला है, जो केवल सरकारों को बेचा जाता है। उनके अनुसार, पेगासस का इस्तेमाल पहले 2019–21 के दौरान विपक्ष के विभिन्न सदस्यों, असंतुष्ट पत्रकारों और नागरिक समाज के सदस्यों के खिलाफ किया गया था। कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद ने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान, विपक्ष के सदस्यों की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और असहमति की आवाज पर लक्षित हमले हुए हैं। उन्होंने कहा कि संचार उपकरणों पर मनगढ़ंत सबूत लगाने के कई मामले सामने आए हैं और राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए निर्दोष नागरिकों को फंसाया गया है। मोइत्रा ने अध्यक्ष से अपील की कि वे विपक्षी सदस्यों को उनके कर्तव्यों को जारी रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा तुरंत प्रदान करें, जो कि सत्तारूढ़ व्यवस्था पर सवाल उठाना और जवाबदेह ठहराना है।

योगी आदित्यनाथ का राजस्थान में चुनावी शंखनाद, कांग्रेस और गहलोत सरकार पर जमकर बरसे

एजेन्सी

जयपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह देश में समस्या का पर्याय बन चुकी है। इसके साथ ही आदित्यनाथ ने राजस्थान में कानून–व्यवस्था को लेकर भी राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वह तिजारा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी व सांसद बाबा बालकनाथ द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि हमने सुना है कि तिजारा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने जिसे उतारा है, वह अपने नाम के साथ बड़ी–बड़ी उपमाएं लगाता है। तालिबान का इलाज तो बजरंग बली की गदा के पास ही है। गाजा पट्टी में तालिबानी मानसिकता को

इजराइल कैसे कुचल रहा है, आप सब देख रहे हैं। कन्हैया लाल के बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप जानते हैं कन्हैया लाल की हत्या कैसे हुई, आप जानते हैं कि अगर ये घटना यूपी में होती तो क्या होता? तुष्टिकरण खत्म होना चाहिए। अशोक गहलोत बस इसी काम में दिन रात लगे हैं। सीएम योगी ने पूछा कि कन्हैया लाल के परिवार को पांच लाख रुपए और गौ तस्करों को बीस–पच्चीस लाख रुपए क्यों दिए गए? आदित्यनाथ ने आरोप लगाया, राजस्थान की गौरवशाली परंपरा को कांग्रेस अपनी प्रकृति के अनुरूप कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस देश के अंदर समस्या का नाम (पर्याय) बन चुकी है। कांग्रेस देश की हर समस्या का नाम (पर्याय) है। उन्होंने कहा, देश जिन समस्याओं का समाधान एक एक कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज कर रहा है वे सभी समस्याएं कांग्रेस की देन हैं। बाबा बालकनाथ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सीएम हाउस फतवा हाउस बन गया है, वहां से सनातन धर्म के खिलाफ काम होते हैं। कांग्रेस सरकार के बारे में बात करने से हमारा मुंह खराब हो जाता है।

इस प्रकार का पांच वर्ष का शासनकाल रहा. धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया। राजगढ़ में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा गया। ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते हैं। किसानों से झूठ बोलकर सरकार बनी है। कांग्रेस सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी दूर करने का लालच दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजाद भारत में सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश का एकीकरण करने के लिए बीड़ा उठाया था। सफल भी हुए, लेकिन कांग्रेस ने देश को कश्मीर की एक समस्या दे दी। अनुच्छेद 370 की एक समस्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री शाह ने समाप्त कर दिया। आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोक दी है। आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त होगा। ये समस्या कांग्रेस की देन है। आदित्यनाथ ने कहा कि समस्या का समाधान करने का नाम ही 'डबल इंजनश की सरकार है। उन्होंने कहा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की 'डबल इंजन की सरकार है ।

सम्पादकीय

लोकतंत्र का प्रहसन

यह अटपटा सा लगता है जब भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ा कानून का अधिकारी यानी अटॉर्नी जनरल कहे कि जनता को राजनीतिक दलों के चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा है 'जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिये।' इस सूत्र–वाक्य से ये कहीं स्पष्ट नहीं होता है कि जनता से ऊपर राजनीतिक दलों का स्थान है। मौजूदा लोकतांत्रिक विसंगतियों व विद्रूपताओं के चलते आज स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि राजनीतिक दल अपने श्वेत–स्याह चंदे के स्रोतों पर जनता से परदादारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में होने वाली सुनवाई से कुछ दिन पहले अटॉर्नी जनरल ने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को भी नीतिगत मुद्दों पर फैसला देने का अधिकार नहीं है। इसी घटनाक्रम के आलोक में यहां उल्लेखनीय है कि देश की शीर्ष अदालत ने समय–समय पर ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं, जिससे देश में पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हो सका है। ऐसे ही ऐतिहासिक आदेश राजनीति में दागी जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में दिये गए हैं। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत द्वारा वर्ष 2003 में दिये गए एक मार्गदर्शक फैसले ने हर दागी प्रत्याशी को बाध्य किया था कि वह अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण सार्वजनिक करे। इस बाबत कोर्ट का कहना था कि यह जानना मतदाता का हक है। कमोबेश यही स्थिति चुनावी चंदा जुटाने के बाबत भी मानी जानी चाहिए। लोकतंत्र की शुचिता इस बात पर निर्भर करती है कि चुनाव की प्रक्रिया में खर्च होने वाला धन कानूनसम्मत स्रोतों से ही मिला हो। यह भी पता हो कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने किन व्यापारिक घरानों तथा उद्योगपतियों से चंदा जुटाया है। ताकि भविष्य में सरकार बनाने पर राजनीतिक दल द्वारा चुनाव के दौरान लिये गए चंदे के एवज में जनता के हितों की कीमत पर लाभ पहुंचाने की कोशिश न की जा सके।

उल्लेखनीय है कि जब संसद में चुनावी बॉन्ड के प्रावधान को कानून का रूप देने का प्रयास किया जा रहा था तो तत्कालीन वित्तमंत्री की दलील थी कि इस कानून के अस्तित्व में आने से जहां चुनाव के लिये चंदा जुटाने में पारदर्शिता आएगी, वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन एजी के बयान से तो कम से कम वह मंशा जाहिर नहीं होती है। निस्संदेह जनता को पता होना चाहिए कि किस राजनीतिक दल ने किस कॉर्पोरेट घराने से कितना चंदा लिया है। इसमें दो राय नहीं कि कॉर्पोरेट घराने भी सत्ता की हवा भांपकर उसी अनुरूप चंदा देते हैं। एक तरह से यह उनका आर्थिक निवेश ही होता है, ताकि कालांतर लोकतंत्र में पूंजीतंत्र का पोषण हो सके। यहां उल्लेखनीय है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर कानूनी प्रावधान है कि चंदा देने वाला व्यक्ति डिजिटल पेमेंट करके एसबीआई के बॉन्ड खरीदता है। कानून के अनुसार राजनीतिक दल व बैंक चंदा देने वाले का नाम उजागर करने के लिये बाध्य नहीं हैं। इसकी वजह से केंद्र सरकार की वित्तीय नियामक संस्थाओं को पता होता है कि कहां से चंदा आया। जिसके चलते सरकार तो जान सकती है कि विपक्षी दल के पास चंदा किस स्रोत से आया है, लेकिन विपक्ष यह नहीं जान सकता कि सरकार को कितना चंदा मिला है और किससे मिला है। जाहिर है इसका लाभ सत्तारूढ़ दल को मिलता है। साथ ही चंदे की ज्यादा मात्रा भी उसके खजाने में आती है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल को कुल चंदे का दो तिहाई हिस्सा मिला है। कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी झलकती है। बहरहाल, लोकतंत्र की शुचिता इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरह संसाधनों से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई है। जाहिरा तौर पर नियम विरुद्ध और अपवित्र स्रोत से अर्जित धन कालांतर लोकतंत्र की पवित्रता पर आंच ही लाएगा। निश्चित रूप से जनता की जागरूकता व न्यायिक सक्रियता ही चुनावी चंदे के धंधे में पारदर्शिता लाने में सक्षम हो सकती है।

सुरक्षित यात्रा की जवाबदेही

हमारी रेल जैसे हादसों का एक सिलसिला बनती जा रही है। एक महीने में दूसरी सबसे बड़ी रेल दुर्घटना होगी और चार महीने में कुल तीनदृतीन तो क्या कहा जाएगा। रविवार की रात आंध्र प्रदेश में दो ट्रेनों की टक्कर और उसमें १४ यात्रियों के मरने और ५० से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। इसके पहलॉ दो जून को बालासोर में तीन ट्रेनों की भिड़ंध्त में सबसे अधिक २९६ यात्री मरे थे और १२०० घायल हुए थे। ११ अक्टूबर को बक्सर में ५ यात्रियों कीदृबाद में इलाज के दौरान एक महिला कीदृमौत हो गई थी तथा १०० घायल हुए थे। और अब विजयवाड़घ की टक्कर में चार महीने में जानमाल की दूसरी बड़घी क्षति हुई है। इससे भारतीय रेलवे और इसे देख रहे मंत्री अश्विन वैष्णव समेत पूरी नरेन्द्र मोदी सरकार जनता के निशाने पर आ गई है। घटनाक्रमों को देखें तो रेलवे औसतन हर महीने किसीदृनदृ किसी हादसों का शिकार रहा हैदृ चलती ट्रेन में आगलगी होॉ पटरी से उतरनॉ कुचल कर मरने और सिगनल पार करने से हुई टक्कर की घटनाएं। इनसे लगता है कि रेलवे में कमांड़ और कार्यप्रणाली में सतर्कता और जवाबदेही को लेकर एक आपराधिक शिथिलता है। इसमें सुधार प्रणाली गैरहाजिर लगती है। उसकी ओर किसी का ध्यान जाता नहीं दिख रहा है। दुर्घटनाएं जिनमें मानवीय क्षति न भी होॉ उसकी बारम्बरता यही जाहिर करती है। विजयवाड़घ में लोको पायलट के सिगनल को ओवर शूट कर जाने यानी उसे पार कर जाने को वजह बताई जा रही है। बालासोर इसका भयंकर दुष्परिणाम है। इसके बाद २५ जून को एक मालगाड़ी सिगनल पार कर पीछे से दूसरी मालगाड़घी से पश्चिम बंगाल के ओंडाग्राम स्टेशन पर टकरा जाती है। इतनी घोर लापरवाही। यह ठीक है कि रेलयात्रियों में प्रतिदिन ४० हजार के इजाफे के साथ रेलवे पर प्रतिदिन १०ॉ३७८ ट्रेनें और ७३३२ मालगाडिघ्ध्यां के परिचालन का दबाव है। फिर कम घंटों में ज्यादा दूरी तय करने के लिए नई रेलगाडिघ्ध्यां भी चलाई जा रही हैं। रेलदृपरिपथ से लेकर डिघ्ब्बों तक का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पर इसके साथ सफर को सुरक्षित बनाना उतना ही बेहद जरूरी है। इसकी नैतिक जवाबदेही रेलवे की है। इसी आधार पर इस्तीफा देने का लालबहादुर शास्त्री से शुरू हुए रिवाज का अंतिम उदाहरण नीतीश कुमार ही है। अब यह दकियानूसी बात हो गई है। पर जबावदेही की बात हमेशा ताजा रहेगी।

तीर्थ : ओशो

तीथ है वहां जाएगा कोई वह मुक्त होकर लौटेगा। तो स्मृति से मुक्त होगॉ स्मृति ही तो बंधन है। वह स्वप्न जो आपने देखॉ आपका पीछा कर रहा है। असली सवाल वही हैॉ और निश्चित ही उससे छुटकारा हो सकता हैॉ लेकिन उस छुटकारे में दो बातें जरूरी हैं। बड़ी बात तो यह जरूरी है कि आपकी ऐसी निष्ठा हो कि मुक्ति हो जाएगी। और आपकी निष्ठा कैसे होगीध्आपकी निष्ठा तभी होगी जब आपको ऐसा खयाल हो कि लाखों वर्ष से ऐसा वहां होता रहा है। और कोई उपाय नहीं है। इसलिए कुछ तीर्थ तो बिल्कुल सनातन हैंदृजैसे काशीॉ वह सनातन है। सच बात यह हैॉ पृथ्वी पर कोई ऐसा समय नहीं रहा जब काशी तीर्थ नहीं थी। वह एक अर्थ में सनातन हैॉ बिल्कुल सनातन है। यह आदमी का पुराने से पुराना तीर्थ है। उसका मूल्य बढ़ जाता हैॉ क्योंकि उतनी बड़ी धाराॉ सजेशन है। वहां कितने लोग मुक्त हुएॉ वहां कितने लोग शांत हुए हैॉ वहां कितने लोगों ने पवित्रता को अनुभव किया हैॉ वहां कितने लोगों के पाप झडई गएदृवह एक लंबी धारा है। वह सुझाव गहरा होता चला जाता हैॉ वह सरल चित्त में जाकर निष्ठा बन जाएगी। वह निष्ठा बन जाए तो तीर्थ कारगर हो जाता है। वह निष्ठा न बन पाए तो तीर्थ बेकार हो जाता है।

विपक्षी नेताओं की फोन टैपिंग

महुआ मोइत्रा समेत कई बड़े नेताओं के फोन सरकार द्वारा टैप करने का विवाद एक बार फिर खड़ा हो गया है। मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी ने यह बात सामने लाई है। दरअसल प्रसिद्ध फोन निर्माता कम्पनी एप्पल का इस्तेमाल करने वाले कई ऐसे विपक्षी नेताओं को कम्पनी की ओर से ईमेल मिला है कि जिसमें चेतावनी दी गई है कि उनके फोन राज्य समर्थित हमलावर (स्टेट स्पॉसर्ड अटैकर्स) द्वारा टैप हो रहे हैं। अनेक विपक्षी नेताओं ने इसकी पुष्टि भी की है। राहुल ने इस बारे में कहा है कि उन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और सरकार चाहे तो बेशक उनका फोन लेकर जा सकती है, परन्तु यह न केवल निजता का हनन है बल्कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाने की भी कोशिश है जिसका विरोध किया जाना चाहिये। मंगलवार को कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि उन्हें अपने आईफोन पर एक अलर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया है कि राज्य प्रायोजित हमलावर उनके फोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसकी प्रतिक्रिया में एप्पल ने कहा है कि वह खतरे से आगाह कर रही है परन्तु इसके लिये किसी भी राज्य–प्रायोजित हमलावर विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही है। अलबत्ता उसका कहना है कि श्ऐसे हैकर्स वित्तीय रूप से बहुत अच्छे से पोषित और परिष्कृत हैं। कम्पनी के अनुसार ऐसे हमलों का पता लगाना कुछ गुप्त संकेतों पर निर्भर करता है जो

ज्यादातर आधे–अधूरे होते हैं। बयान में यह भी साफ किया गया है कि संभव है कि कुछ सूचनाएं गलत चेतावनी हो सकती हैं या कुछ हमलों का पता न चल पाए। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह इस बारे में जानकारी देने में असमर्थ है कि किस कारण से उसे एलर्ट जारी करना पड़ा है क्योंकि इससे राज्य प्रायोजित हमलावर भविष्य में और सावधान होकर काम करेंगे। इस जानकारी के सार्वजनिक होने से हड़कम्प मच गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनका डिवाइस हैक हो रहा है या उसकी निगरानी हो रही है। ऐसे ही, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी को भी सोमवार की रात एप्पल से एक ई–मेल मिला। उसमें भी सावधान किया गया है कि उनके फोन की राज्य–प्रायोजित निगरानी की जा रही है और उनका फोन और सभी सिस्टम हैक हो रहे हैं।श वैसे कम्पनी द्वारा इस हैकिंग से निपटना मुश्किल बताया गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना (उद्धव गुट) की प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस के लोकसभा सदस्य शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी आदि ने भी ऐसी ही चेतावनी मिलने की पुष्टि की है। कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किये हैं जिसके बाद शक की गुंजाईश नहीं रह जाती है कि यह काम केन्द्र सरकार की ओर से ही हो रहा है। अब तक सरकार की ओर से कोई बयान न आना भी उसे शक के घेरे में डालता है। आखिरकार भारत के प्रतिपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग में और किस देश की सरकार की रुचि हो सकती है? राहुल गांधी ने इस बात को और स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कारोबारी मित्र गौतम अदानी के खिलाफ बोलने के कारण ही उनके फोन को टैप किया जा रहा है। उनकी बात में इसलिये दम दिखता है क्योंकि जितने लोगों को भी निर्माता कम्पनी द्वारा फोन टैपिंग की चेतावनी वाले ईमेल मिले हैं वे न केवल विपक्ष के हैं वरन बेहद मुखर भी हैं और अदानी के विरूद्ध आवाज भी उठाते रहे हैं। उनके द्वारा मोदी सरकार की आलोचना के अंतर्गत अदानी प्रमुख विषय होते ही हैं। अपने फोन की टैपिंग के एलर्ट का संदेश देने वाले ईमेल की प्रति दिखाते हुए राहुल ने यह भी कहा कि देश में मोदी के भी ऊपर अदानी हैं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से इस बात की घोषणा कर दी कि चाहे जो हो जाये, वे अदानी–मोदी के कथित घोटालों को उठाते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पहले भी भारत सरकार पर यह आरोप लग चुका है कि उसने इजरायल से पैगासस नामक जासूसी उपकरण खरीदा है जिसके जरिये देश के अनेक लोगों के फोन टैप कराये जा रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों के नाम सामने आये थे उनमें सिर्फ विपक्षी दल के नेता ही नहीं बल्कि नितिन गडकरी जैसे कुछ उनके अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी भी थे। उनमें कुछ पत्रकार और यहां तक कि भूतपूर्व न्यायाधीश के नाम भी सामने आये थे। हालांकि उस समय भी सरकार ने इस बात से इंकार किया था कि वह किसी के फोन टैप करा रही है लेकिन उसका खुलासा जिस प्रामाणिक ढंग से हुआ था, उससे शक की कोई गुंजाईश नहीं रह जाती थी। सम्भवतया मामला उठने के बाद उतने ही गुपचुप तरीके से उसका इस्तेमाल रोक भी दिया गया होगा। हालांकि कोई इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकता कि वह जासूसी रोक दी गई होगी।

जो भी हो, यह एक गम्भीर मसला है और सरकार को चाहिये कि इस बात की गहराई से और पारदर्शितापूर्वक जांच कर इसकी रिपोर्ट जनता के सामने लाए। हालांकि इसकी मोदी सरकार से इसकी उम्मीद करना बेकार है। सम्भव है कि सरकार इस पर मौन धारण कर ले और आतंक फैलाने हेतु यह भ्रम बनाकर रखे कि विपक्षियों के फोन टैप हो रहे हैं।

धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद लोकतंत्र के लिए विनाशकारी

संजीव ठाकुर

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैस स्वतंत्रता के बाद से भारत के संविधान में लोकतंत्र को सर्वोपरि स्थान दिया गया हैस देश की भौगोलिक तथा जनसंख्यात्मक विशालता में कुछ तत्व सांप्रदायिक हिंसा एवं अराजकता के परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकतें हैं, पर भारतीय लोकतंत्र की महानता एवं विशालता है कि इससे संवैधानिक भारतीय लोकतंत्र को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर यह तय है कि सांप्रदायिक हिंसा एवं धार्मिक कट्टरता से लोकतंत्र की अवधारणा थोड़ी दिग्भ्रमित जरूर होती है पर इसकी मजबूती ना तो पहले कम हुई है और ना ही भविष्य में होने की कोई गुंजाइश ही है। हिंसा ,विवाद किसी भी बात का कोई हल नहीं। यह लोकतंत्र के लिए एक धब्बे के समान है। किसी भी देश में लोकतंत्र की आम धारणा आपसी सद्भाव और समभाव को लेकर आधारभूत रचनात्मक रूप से की गई है। विश्व के शांति प्रस्तावक भारत देश में हिंसा और हिंसक आंदोलन की कोई जगह नहीं एवं यह किसी धार्मिक, सामाजिक अथवा आर्थिक असहमति का परिणाम तो कतई नहीं हो सकती है।भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक,प्रजातांत्रिक स्वतंत्र राष्ट्र है।वैचारिक चिंतन, प्रभुद्धता लोकतंत्र के प्रमुख अवयव होते हैं, राष्ट्र के किसी भी नीति में सहमत और असहमत होना एक सामान्य प्रक्रिया, प्रतिक्रिया हो सकती है, और आम जनमानस का किसी मुद्दे पर आप सहमत होना भी एक सामान्य बात हो सकती है पर किन्ही भी परिस्थितियों में असहमति हिंसा के रूप में कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं होनी चाहिए, विरोध का स्वरूप राष्ट्रीय संपत्ति की बर्बादी तो किसी भी काल और खंड में स्वीकार्य नहीं है। यह राष्ट्र के लिए घातक और विकास की अवधारणा को अवरुद्ध करने वाला आत्मघाती कदम है।आंदोलन का स्वरूप सदैव शांति पूर्वक हो तो राष्ट्र तथा आमजन के हित में ही होगा। आंदोलनकारियों को शायद यह गुमान नहीं है कि राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति आपके द्वारा दिए गए टैक्स के रूप में रुपयों से ही निर्मित होती है, इसे नष्ट करके आप स्वयं अपनी संपत्ति का नुकसान ही कर रहे हैं। आजादी के बाद से भारत के समक्ष कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं आई है। अक्सर सामाजिक क्षेत्र में समस्याओं ने अर्थव्यवस्था की उत्तरोत्तर प्रगति पर अवरोध खड़े किए हैंस देश की सामाजिक विषमताओं ने समाज में कई समस्याओं को जन्म दिया है एवं आर्थिक प्रगति पर विभिन्न सोपानों में लगाम लगाई है। भारतीय समाज में विषमता एवं विविधता भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी है। स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में विषमताएं भारत के लिए चुनौती बनकर वर्तमान में कई बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। आज जातिगत संघर्ष बढ़ गए हैं,जातिगत संघर्षों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने बहुत क्लिष्ट बना दिया है। राजनीति सदैव महत्वाकांक्षा के बल पर जातिगत समीकरण को नए–नए रूप तथा

आयाम देती आई है और सदैव समाज में वर्ग विभेद आर्थिक विभेद कर के अपना उल्लू सीधा करना मुख्य ध्येय बन चुका है। उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग सदैव सत्ता के संघर्ष के लिए न सिर्फ एक दूसरे का परस्पर विरोध करते है बल्कि शासन प्रशासन के विरोध में भी सदैव खड़े पाए गए हैं। सत्ता पाने की लालसा में जातीय संघर्ष, नक्सलवाद तेजी से समाज में पनपता जा रहा है। भारतीय परिपेक्ष में आज सिर्फ जाती ही नहीं धार्मिक महत्वाकांक्षा देश के समाज के समक्ष चुनौती बन गया है। भारत में हिंदू मुस्लिम जाति संघर्ष ऐतिहासिक तौर पर अपनी जड़ें जमां चुका है, वर्तमान में मंदिर और मस्जिद के झगड़े देश में अशांत माहौल पैदा करने का एक बड़ा सबक बन चुके है।और यही वर्ग विभेद संघर्ष भारतीय आर्थिक विकास के बीच एक बड़ा अवरोध बनकर खड़ा है। पश्चिमी विद्वान भी कहते हैं कि भारत के राष्ट्र के रूप में विकसित होने में जाति एवं धर्म ही सबसे बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना सर्वाधिक कठिन कार्य है क्योंकि इसकी जड़ें भारत के स्वतंत्रता के पूर्व से देश में गहराई लिए हुए हैं। जातीय वर्ग संघर्ष और भाषाई विवाद ऐसा मुद्दा रहा है जिससे लगभग एक शताब्दी तक भारत आक्रांत रहा है। आजादी के बाद से ही भाषा विवाद को लेकर कई आंदोलन हुए खासकर दक्षिण भारत राज्यों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने एवं देश पर हिंदी थोपे जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शनों को प्रोत्साहित किया गया। आज भी विभिन्न राज्यों में भाषाई विवाद एक ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, चाहे वह बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी भाषाई विवाद अलग–अलग स्तर पर सतह पर पाए गए हैं। समान सिविल संहिता को लेकर बहुसंख्यक संविधान में आक्रोश है दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय इसलिए डरा हुआ है कि कहीं उसकी अपनी अस्मिता एवं पहचान अस्तित्व हीन ना हो जाए। स्वतंत्रता के बाद से यह विकास की मूल धारणा थी कि पंचवर्षीय योजनाओं में वर्ग विहीन समाज में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष तरीके से समाज का आर्थिक विकास तथा रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। पर स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वर्ग विभेद भाषाई विवाद ने अभी भी आर्थिक विकास में कई बाधाएं उत्पन्न की है।

संविधान में सदैव सकारात्मक वर्ग विभेद एवं विकास की अवधारणा को प्रमुखता से शामिल किया गया था और पंचवर्षीय योजनाओं में भी विकास को वर्ग विभेद से अलग रखकर विकास की अवधारणा को बलवती बनाया गया है। सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक विविधता वाले समाज को विवादों से परे रख आर्थिक विकास की परिकल्पना एक कठिन और दुष्कर अभियान जरूर है पर असंभव नहीं है। और इसी की परिकल्पना को लेकर आजादी के पश्चात से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रादुर्भाव सरकार ने समय–समय पर लागू किया है।

विकास की अवधारणा में राष्ट्र की मुख्य धारा में समाज के पिछड़े वर्ग को शामिल कर उन्हें सम्मुख लाना होगा। यदि देश के पिछड़ा वर्ग और गरीब तबका विकास की मुख्यधारा से जुड़ता है तो गरीबी, भुखमरी, नक्सलवाद जैसे संकट अस्तित्व हीन हो जाएंगे और ऐसी समस्या धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आवश्यकता यह है कि हमें राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानकर इस पर अमल करना होगा। फिर चाहे वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो या समावेशी राष्ट्रवाद हो। समाज की मुख्यधारा में राष्ट्रवाद को एक प्रमुख अस्त्र बनाकर देश की प्रगति में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत में आजादी के 75 वर्ष बाद भी ब्रिटिश हुकूमत की तरह गरीबी, भूखमरी ,बेरोजगारी ,नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता,भाषावाद एवं क्षेत्रीय विघटनकारी प्रवृत्तियां सर उठाये घूम रही हैं, हम इन पर अभी तक प्रभावी नियंत्रण नहीं लगा पाए हैं। हमें इन सब विसंगतियों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय नागरिकता एवं भारत राष्ट्र की विकास की अवधारणा को राष्ट्रवाद से जोड़कर आर्थिक विकास को एक नया आयाम देना होगा,तब जाकर भारत वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत एवं आत्मनिर्भर बन सकेगा। किसी बात का विरोध हिंसा के बिगड़े स्वरूप की तरफ शासकीय संपत्ति को नष्ट करना देश हित में नहीं।

मराठा आरक्षण की आग

जब आरक्षण के प्रावधान संविधान में जोड़े गए तब वे न तो जाति को लेकर थे न ही ध्आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर। तब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने की बात थी। तब यह माना गया कि आर्थिक पिछड़ापन दूर करना सरकार का फर्ज है इसलिए आरक्षण को गरीबी दूर करने का हथियार नहीं समझा गया था। बाद में वोट बैंक की राजनीति के चलते आरक्षण ऐसा अमृत का प्याला हो गया जिसे छूकर हर जाति अपनी समस्याओं को दूर करना चाहती है। इस देश ने आरक्षण आंदोलन के हिंसक दौर को एक बार नहीं कई बार देखा है। आरक्षण की आग में समाज पहले भी कई बार झुलस चुका है। चाहे वह हरियाणा के जाटों का आंदोलन हो, गुजरात में पटेल समुदाय का आंदोलन हो, राजस्थान के गुर्जर समुदाय का आंदोलन हो, आंध्र प्रदेश के कापू समुदाय का आंदोलन हो। आंदोलन जब हिंसक होते हैं तो न केवल लोगों की जानें जाती हैं बल्कि राष्ट्र की सम्पत्ति को भी नुक्सान पहुंचता है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन एक बार फिर हिंसक हो गया है। राज्य में अलग–अलग जगहों पर दो विधायकों के और एक मंत्री के घर को आग लगा दी गई। दर्जनों वाहन फूंक डाले गए। राकांपा का कार्यालय जला दिया है। बीड समेत कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। आरक्षण की मांग को लेकर लोग आत्महत्याएं करने लगे हैं और विधायक और सांसद इस्तीफे दे रहे हैं। आंदोलन के हिंसक होने से राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार की मुसीबत और बढ़ गई है। मुख्यमंत्री शिंदे मराठा हैं। उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडण्वीस और राकांपा दिग्गज शरद पवार भी मराठा हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी अपील पर आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। महाराष्ट्र में करीब 32 साल पहले मराठा आरक्षण को लेकर पहली बार आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन मराठी लेबर यूनियन के नेता अन्नासाहब पाटिल की अगुवाई में हुआ था। उसके बाद से मराठा आरक्षण का मुद्दा यहां की राजनीति का हिस्सा बन गया। महाराष्ट्र में ज्यादातर समय मराठी मुख्यमंत्रियों ने ही सरकार चलाई है लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। जबकि 2014 के चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लेकर आए थे लेकिन 2014 में कांग्रेस–एनसीपी गठबंधन की सरकार चुनाव हार गई और बीजेपी–शिवसेना की सरकार में देवेंद्र फड़णवीस मुख्यमंत्री बने। फड़णवीस की सरकार में मराठा आरक्षण को लेकर एमजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना। इसकी सिफारिश के आधार पर फड़णवीस सरकार ने सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट के विशेष प्रावधानों के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया। फड़णवीस की सरकार में मराठाओं को 16 प्रतिशत आरक्षण मिला लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13 प्रतिशत और शैक्षणिक संस्थानों में 12 प्रतिशत कर दिया। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। दरअसल, मराठा समुदाय का कहना है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुनबी माना जाता था और ये ओबीसी थे, इसलिए फिर से इन्हें कुनबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। यह लड़ाई लंबे समय से चल रही है लेकिन ऐसा नहीं कि राज्य सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया हो। महाराष्ट्र सरकार मराठाओं को आरक्षण देने की पूरी कोशिश में है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा सीमित कर रखी है, वह सरकार के लिए रोड़ा बनी हुई है। महाराष्ट्र में लगभग 30 फीसदी मराठा समुदाय की आबादी है। सामाजिक और आर्थिक रूप से यह समुदाय काफी पिछड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा संस्थानों और नौकरियों में मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) की साल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में करीब 37.28 फीसदी मराठा गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहते हैं। इस समुदाय का 76 फीसदी समुदाय कृषि और कृषि श्रम पर निर्भर करता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से 2013 से 2018 तक 2152 मराठा समुदाय के किसानों ने आत्महत्या की। इस खुदकुशी की मुख्य वजह कर्ज और फसल की बर्बादी थी। मराठा आरक्षण आंदोलन के पीछे भी कई कारण हैं। एक मुद्दा आरक्षित वर्गों व जातियों के क्रीमी लेयर का है जो सारा फायदा लेकर जा रहा है। इससे युवाओं में नाराजगी बढ़ी है। उन्हें लगता है कि 90 फीसदी अंक लाकर भी उनका दाखिला अच्छे संस्थानों में नहीं होता, जबकि अपेक्षाकृत काफी कम अंक लाकर आरक्षण के बूते पर दूसरी जातियां लाभ उठाती हैं। अब यह पड़ताल करने का समय आ गया हैध कि आज हमारा समाज वास्तव में कितना पिछड़ा है और उसे आरक्षण की कितनी जरूरत है। अगर हम जाति युद्ध से बचना चाहते हैं तो हमारे नीति निर्माताओं को ठोस कदम उठाना होगा। एक ऐसा राष्ट्रीय आयोग बनना चाहिए जो तमाम मुद्दों को परखे और आरक्षण उन्हें ही दिया जाए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत हो। आरक्षण का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी ले चुके लोगों को इससे वंचित किया जाना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। यह काम वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए न होकर ईमानदारी से किया जाना चाहिए।

18 वर्ष से अधिक आयु के सभी युवक युवतियां मतदाता सूची में दर्ज कराये नाम : जिलाधिकारी

1-मतदाता पंजीकरण कक्ष के माध्यम से मतदाताओं को किया जा रहा जागरुक

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारीधजिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा के नेतृत्व में चल रहे स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम सर्वोदय इन्टर कालेज खुदौली में आयोजित किया गया। जिसमें लोगों को मतदाता पंजीकरण के लिए जागरुक किया गया। छात्रों ने रंगोली बनाकर व पोस्टर बनाकर भी मतदाता बनने हेतु प्रेरित किया।

इस अवसर पर कालेज में मतदाता पंजीकरण कक्ष (मतदाता हेल्प डेस्क) स्थापित किया गया। जिसका उदघाटन मुख्य अतिथि खण्ड शिक्षा अधिकारी शाहगंज अमरदीप जायसवाल ने फीता काट कर किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि कालेज में अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी युवक-युवतियों का मतदाता सूची में नाम जुड़वाना सुनिश्चित करें। मतदाता बनने के लिए फार्म-6 के माध्यम से आवेदन करायें। तथा मतदाता सूची में यदि मृतक का नाम दर्ज है तो उनके नाम निकालने हेतु फार्म-7 भरवाये, तथा शिफ्टेड मतदाता या जिनका नाम मतदाता सूची में पहले से कही हैं और अब वे किसी अन्य शहरध विधानसभाध्योलिंग बूथ पर वोटर बनना चाहतें हैं तो फार्म 8 भरकर आवेदन कराये।

प्रधानाचार्य डा अनिल कुमार उपाध्याय ने कहा कि आज ही मतदाता के रुप में अपना नाम पंजीकृत करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भागीदारी बने। लोगों की सुविधा हेतु कालेज में मतदाता पंजीकरण कक्ष खोला गया है। जिसमें वोटर बनने के लिए जागरुक किया जा रहा है। तथा विशेष तिथियों 4, 5, 25, 26 नवम्बर व 2, 3 दिसम्बर को बीएलओ मतदान केंद्रों पर उपस्थित होकर दावे व आपत्तियां प्राप्त करेगी। उन्होंने समस्त छात्र छात्राओं से कहाँ कि ये सुनिश्चित करें कि उनके परिवार के 18 वर्ष से ऊपर सभी सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है और जिनके नाम सम्मिलित नहीं हैं, उनके नाम सम्मिलित किये जाने हेतु समय से आनलाइन या आफलाइन आवेदन कराये।

स्वीप कोआर्डिनेटर सैय्यद मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि विध ानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 का अभियान 27 अक्टूबर से चल रहा है जो कि 9 दिसम्बर 2023 तक चलेगा। इसलिए महिला, पुरुष, दिव्यांग, तृतीय लिंग व युवा जो दिनांक 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले हो या जिनका नाम वोटर लिस्ट में छूटा हो वे अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराये। आवेदन बीएलओ के माध्यम से करें एंव वोटर सर्विस पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं,

तथा पहले से पंजीकृत वोटर मतदाता सूची में अपना नाम भी जांच सकते है। उन्होंने सभी डिग्री व इन्टर कालेज से अपील किया कि अपने कालेज में मतदाता पंजीकरण कक्ष स्थापित करके मतदाता पंजीकरण अभियान में सहयोग प्रदान करें।

संचालन दिनेश कुमार गुप्ता ने किया। इस अवसर पर खण्ड विकास अधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह, अनिल कुमार सिंह, नोडल अजय कुमार, विनोद मिश्रा, प्रशांत मिश्र, अशोक मौर्य, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश द्विवेदी, राजेश यादव, रेखा यादव सुगीता सिंह, किरन सिंह, सर्वोदय इन्टर कालेज, वासुदेव तपेश्वरी, आदर्श भारतीय महाविद्यालय के शिक्षक व छात्र छात्राएं आदि उपस्थित रहें।

संगत पंगत व कायस्थ महासभा ने राकेश सिन्हा एडवोकेट को श्रंद्धाजलि अर्पित किया

मंत्री गिरीश चन्द यादव व अधिवक्ता संघ जौनपुर के सभी संगठनों ने भी शोक व्यक्त किया।

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। रुहट्टा निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता व चित्रगुप्त सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश सिन्हा जी का निधन हो गया अंतिम संस्कार रामघाट पर हुआ अंतिम संस्कार में अधिवक्ता संघ व समाज के लोगो ने भाग लिया व विभिन्न जगहों पर शोक सभा का आयोजन भी हुआ उसी कड़ी में एक शोक सभा संगत पंगत परिवार व अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 2150 ने व कायस्थ समाज जौनपुर ने चित्रगुप्त धर्मशाला में किया। कर्मचारी नेता व कायस्थ महासभा 5680 के जिलाध्यक्षध्प्रदेश महासचिव राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इधर एक माह में कई कायस्थ परिवार में निधन हुआ जिससे समाज मर्माहित हैं राकेश सिन्हा जी हमेशा समाज की सेवा में समर्पित रहते थे। वरिष्ठ अधिवक्ता सरस चन्द श्रीवास्तव व कायस्थ महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव एडवोकेट व जिलाध्यक्ष कायस्थ महासभा 2150 मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि राकेश सिन्हा जी जिले के सम्मानित अच्छे अधिवक्ता थे व कानून के अच्छे जानकार थे अधिवक्ताओ को हमेशा प्रोत्साहित करने का कार्य किया है।कायस्थ महासभा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव साध ु व कायस्थ महासभा के जिला महासचिव सुरेश अस्थाना ने श्रंद्धाजलि देते हुए कहा कि राकेश सिन्हा जी हमेशा सबके सुखदुःख में दिखते थे अब उनकी कमी समाज को खलेंगी ।कायस्थ समाज के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन श्रीवास्तव जी ने कहा कि राकेश सिन्हा जी समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। कायस्थ महासभा 2150 के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव पूर्व प्रशासनिक अध िकारी व प्रदेश सचिव उमेश चन्द श्रीवास्तव ने कहा की समाज में इनके परिवार के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता।चित्रगुप्त सभा के अध्यक्ष रमेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने कहा कि चित्रगुप्त सभा की बड़ी छती हुई हैं जिसे कभी पूरी नहीं कि जा सकती। संगत पंगत के वरिष्ठ कार्यकर्ता अजय वर्मा अज्जू ने कहा कि राकेश सिन्हा एडवोकेट ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया उनकी कमी समाज को हमेशा खलेगी। संगत पंगत के वरिष्ठ नेता व कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय महासचिव राजेश श्रीवास्तव बच्चा भइया एडवोकेट ने कहा कि आज जो चित्रगुप्त धर्मशाला बना है उसमें स्व रामचंद्रर सिन्हा बाबुजी परिवार का बड़ा योगदान है उसी परंपरा को राकेश सिन्हा एडवोकेट ने भी आगे बढ़ाया मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।कायस्थ महसभा के राष्ट्रीय युवा सचिव वरिष्ठ पत्रकार विश्व प्रकाश श्रीवास्तव दीपक व पत्रकार अंकित श्रीवास्तव ने कहा कि संगत पंगत परिवार सुखदुःख में सबके साथ खड़ा रहता है राकेश सिन्हा एडवोकेट जी हमेशा समाज के साथ खड़े रहे। उनका जाना समाज के लिये अपूरणीय क्षति हुई है।जिसको भरा नही जा सकता है। श्रंद्धाजलि अर्पित करने वाले में वरिष्ठ अधिवक्ता व चित्रगुप्त सभा के वरिष्ठ पदाधिकारी श्यामलकान्त श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव एडवोकेट,अनीश श्रीवास्तव, ,अतुल श्रीवास्तव ऑडिटर दीवानी अधिवक्ता संघ, शिव शंकर लाल ऑडिटर कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ,मोहन शंकर श्रीवास्तव,संदीप श्रीवास्तव पत्रकार,अनुराग श्रीवास्तव एडवोकेट गिरिजेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ नेता संगत पंगत संतोष श्रीवास्तव वी आर पी, अनिल श्रीवास्तव ,प्रदीप श्रीवास्तव,अमित श्रीवास्तव,हरिश्चंद्र श्रीवास्तव अनिल श्रीवास्तव वरिष्ठ नेता संगत पंगत संतोष निगम ,संदीप श्रीवास्तव पत्रकार,अनीश श्रीवास्तव,डॉ प्रतिमा श्रीवास्तव,आर पी श्रीवास्तव,अतुल श्रीवास्तव,राकेश कुमार श्रीवास्तव, शिव शंकर श्रीवास्तव,अजय श्रीवास्तव,मनीष श्रीवास्तव,राजेश श्रीवास्तव,संजय श्रीवास्तव प्रदीप श्रीवास्तव शिवम श्रीवास्तव, राजन श्रीवास्तव, धीरज श्रीवास्तव सहित आदि लोगो ने श्रंद्धाजलि अर्पित किया। वही प्रातः राकेश सिन्हा जी के आवास पर कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनोज मिश्रा एडवोकेट अपने पदाध िकारी व अधिवक्ताओ के साथ आवास पर पहुचकर राकेश सिन्हा अधिवक्ता के शव पर पुष्पांजली अर्पित करते हुए श्रंद्धाजलि अर्पित किया। वही राकेश सिन्हा एडवोकेट के निधन पर एक शोक संदेश में प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश चन्द यादव जी, पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह, नगर पालिका अध यक्ष मनोरमा मौर्य भाजपा नेता डॉ रामसूरत मौर्य ने भी शोक संवेदना व्यक्त किया है।

एयरटेल ने उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया इनोवेटिव मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्लैटफॉर्म एयरटेल आइक्यू रीच

अब उत्तर प्रदेश में व्यापारी पूर्व-निर्धारित ग्राहकों तक व्यक्तिगत सन्देश भेज सकेंगे व किफायती लागत में अपने ग्राहकों की सहभागिता पर अधिक नियंत्रण का आनंद उठा सकेंगे

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। भारत की प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों में से एक, भारती एयरटेल ("एयरटेल") ने आज उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लैटफॉर्म – एयरटेल आइक्यू रीच लॉन्च करने की घोषणा की।

छोटे व मध्यम वर्ग के व्यवसाई (एसएमबी) को उनके ग्राहकों की आवश्यकतानुसार सहभागिता रणनीति के अनुरूप अपने वव्यवसाइक संदेशों को बेहतर बनाने की क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किये गए इस प्लैटफॉर्म से शहर में व्यवसाईयों को किफायती तरीके से अपने-अपने लक्षित ग्राहकों तक पहुँचने में आसानी होगी।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, रेस्तरां और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़े व्यवसाय अब बस https://www-airtel-in/business/b2b/airtel&iq/dashboard/#/ पर वन स्टॉप डेस्टिनेशन पर लॉग इन कर सकते हैं।

अनुकूलित संदेशों को डिजाइन करने से लेकर अपने लक्षित ग्राहकों को अपलोड करने या चुनने, उनके संदेशों को शेड्यूल करने और अंत में, मार्केटिंग कैंपेन की प्रभावशीलता को ट्रैक करने तक, व इसे आसानी से प्रबंधित और पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए, बस कुछ ही क्लिक में यह प्लैटफॉर्म एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड पर रियल-टाइम जानकारी और व्यापक विश्लेषण भी प्रदान करेगा। इससे वव्यवसाइयों को अपने प्रचार को प्रभावकारी ढंग से मापने की क्षमता हासिल होगी। यह पोर्टल व्हाट्सऐप और एसएमएस के जरिए संदेशों के लिए चालू हो गया है। जल्द ही इसे वॉइस और दूसरे चौनलों पर भी आरम्भ किया जाएगा।

एयरटेल बिजनेस के हेड-डिजिटल प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज, अभिषेक बिस्वाल ने कहा कि, "एयरटेल के हर कार्य के केंद्र में ग्राहक होते हैं। हमने एयरटेल आइक्यू रीच को खासकर नये उभरते व्यावसाई वर्ग के लिए डिजाइन किया है, ताकि उन्हें अपने ग्राहक अनुरूप संदेशों को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। यह प्लैटफॉर्म लक्षित ग्राहकीय संदेशों में उपक्रमों को सुविध ा प्रदान करने के लिए एयरटेल के इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता की शक्ति के साथ-साथ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ उठाता है। उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक संगठन और कारोबारी अब अपने व्यावसाय की वृद्धि के लिए इस प्लैटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। इससे उन्हें अपनी ग्राहक अधिप्राप्ति लागत कम करने और हमारे अभिनव समाधान के माध्यम से सही व्यक्तिगत सन्देश के द्वारा सही समय पर सही ग्राहक को लक्षित करने में आसानी होगी।"

एयरटेल आइक्यू रीच व्यवसायों को सही ग्राहक वर्ग की पहचान करना, प्रचार की प्रभावकारी ट्रैकिंग करने, अपने ग्राहकों तक पहुँचने के लिए कई चौनलों को सँभालने आदि जैसी मार्केटिंग से जुड़ी विज्ञापन-प्रचार की योजना बनाते समय होने वाली मुख्य कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलेगी।

एयरटेल आइक्यू रीच एक ओमनी-चौनल क्लाउड कम्युनिकेशन प्लैटफॉर्म है जो क्लाउड कम्युनिकेशन तथा ग्राहक अनुभव प्रबंधन को एकीकृत करके वॉइस, एसएमएस और व्हाट्सऐप चौनलों में अपने ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए ब्रैंड्स को सक्षम बनाता है। एयरटेल विश्व में पहली टेलीकॉम कंपनी है जो व्हाट्सऐप के लिए एक बिजनस सर्विस प्रोवाइडर (बीएसपी) का काम करती है।

लंका को धू धू जलता देख जयकारों से गूँज उठा पंडाल

मोहरियांव का अटूट प्रेम है जो मुझे रामलीला में आने का अवसर मिला - सैयद हुसैन मुन्तजर

सुजानगंज (जौनपुर)। क्षेत्र के मोहरियाँव गांव में चल रहे आदर्श रामलीला धर्म मंडल समिति का शुभारंभ मणि शंकर यादव ने किया और वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था मे तैनात पुलिस कर्मियों के निरीक्षण के दौरान उपस्थित थानाध्यक्ष सुजानगंज सैयद हुसैन मुंतजर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए नारी सुरक्षा पर विशेष चर्चा किया और कहा कि मोहरियांव के रामलीला और मोहरियाँव के लोगों का ऐसा अटूट प्रेम रहा कि मुझे यहां आने पर विवश होना पड़ा और मैं हमेशा के लिए यह लिखकर जाऊंगा की जीवन भर जब तक रामलीला होगा तब तक यहां पर जितने दिनों तक होगा उतने दिनों तक सुरक्षा व्यवस्था थाने से प्रदान की जाएगी और सभी रामलीला के कलाकारों का ह्रदय से धन्यवाद कि आप लोग परंपराओं को बचाये. वहीं पर रामलीला में राम सुग्रीव मिलन, बाली बध, हनुमान जी का लंका जाना, लंका दहन का हुआ मंचन। रामलीला मंचन में समुंद्र के किनारे जामवंत, हनुमान वानरी सेना के साथ खड़े रहते है तो जामवंत ने हनुमान के बाल्यकाल की ताकत का एहसास दिलाया तो हनुमान जी जय श्री राम का जयकारा लगाकर समुद्र को पर करके लंका के लिए चल देते है ।

और लकिनी और विभीषण से मुलाकात हुई फिर अपनी भूख को मिटाने के लिए अशोक वाटिका पहुंचे हनुमान जी ने वहाँ लगे पेड़ पौधे उखाड़ने लगे तो इसकी सूचना रख वालों ने रावण को दी मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म फाँस में बांध ाकर दरबार में ले आए रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई हनुमान जी ने पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने सोने की पूरी लंका में आग लगा दी लंका धू-धू कर जलने लगी और वह कुछ ही देर में जलकर राख हो गई यह दृश्य देख प्रभु श्री राम व पवनसुत हनुमान की जय कारों से रामलीला मैदान गूंज उठा।

इस अवसर पर विशंभर नाथ दुबे, भास्कर मणि तिवारी,राकेश यादव, चंदन मिश्र, पवन गुप्ता, मयंक मिश्र, सोनू तिवारी, कार्तिकेय विश्वकर्मा, ईश्वर दुबे, सिंटू मिश्रा, बाबा मिश्रा, मोनू विश्वकर्मा, बिल्लू गुप्ता, बड़े चौबे, मोनू तिवारी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

नारी शक्तिवंदन अधिनियम पारित होने के बाद नारी शक्तिका सम्मान बढ़ा है:-मुख्यमंत्री

'सामान्य शिक्षक से लेकर चंद्रयान की उड़ान तक आधी आबादी की भागीदारी है:-योगी आदित्यनाथ'

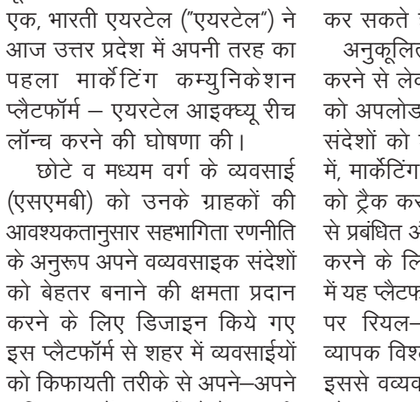

'रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' मिशन शक्ति फेज-4 के अंतर्गत आज माननीय मुख्यमंत्री का आगमन जनपद की नारी शक्ति के मध य उधरनपुर शाहाबाद में हुआ। हेलीपैड पर उतरने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों के स्टालों का अवलोकन किया। बाल सेवा पुष्टाहार विभाग के स्टॉल के अंदर उन्होंने 3 बच्चों को अन्नप्राशन एवं 3 महिलाओं की गोदभराई करायी। प्रदर्शनी स्थल पर उन्हेंने दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल एवं अन्य दिव्यांग उपकरण प्रदान किये। एफपीओ से जुड़ी चार महिला किसानों को उन्होंने ट्रैक्टर की चाभी प्रदान की। माननीय मुख्यमंत्री ने मंच पर विभिन्न योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं को प्रमाणपत्र एवं उपकरण प्रदान किये। एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत उन्होंने लाभार्थियों को टूल किट प्रदान किये। उन्होंने पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रुचि त्रिवेदी को खेलकिट प्रदान की। कार्यक्रम में मा0 मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर 541 करोड़ रुपये लागत की 217 परियोजनाओं का उद्घाटन व लोकार्पण किया। अपने संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा है और प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को देश के एजेंडा का हिस्सा बनाया। उनके स्वाभिमान व स्वावलंबन से जुड़ी योजनाएं चलाई। हर घर शौचालय की व्यवस्था की गयी। निर्धनों को आवास, मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए। एक सामान्य शिक्षक से लेकर चंद्रयान की उड़ान तक आधी आबादी की भागीदारी है। परिसीमन के उपरांत नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को हिस्सेदारी मिलेगी। आने वाले समय मे बचे हुए निर्धन परिवारों को आवास मिलेगा। प्रध ानमंत्री स्वामित्व योजना से सभी को जमीन का मालिकाना रिकॉर्ड प्राप्त होगा। पीएम स्वानिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 14 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं जिसमे से ज्यादातर महिला लाभार्थी हैं। उन्होने कहा कि शोषण मुक्त भारत का सपना साकार हो रहा है और पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या 10 हजार से बढ़कर 40 हजार हो गयी है तथा खेलो इंडिया प्रोग्राम में विश्व स्तरीय खेलों में पदकों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने महिला खिलाड़ी पारुल चौधरी का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय मे प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों की संख्या बढ़ाने के लिए कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है। मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गयी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब 3 लाख से अधिक महिलाओं की शादी हो चुकी है। निराश्रित महिला पेंशन पेंशन योजना में 29 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। उन्होंने आयुष्मान योजना, हर घर नल योजना व अन्य विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक योजना से बड़ी संख्या में प्रदेशवासी लाभान्वित हुए हैं। इस अवसर पर मा0 सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर एवं मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने भी जनसभा को सम्बोधित करते हुए भारत एवं प्रदेश सरकार की उपलधियों के बारे में बताया। कार्यकम्र में मा0 मंत्री आबकारी एवं मद्य निषेध नितिन अग्रवाल, सांसद जय प्रकाश रावत, अशोक रावत, अशोक बाजपेई, जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती, मा0 विधायक अलका अर्कवंशी, रामपाल वर्मा, श्याम प्रकाश, माधवेन्द्र प्रताप सिंह रानू, प्रभाष कुमार, आशीष कुमार सिंह आशू, अशोक अग्रवाल, अवनीश सिंह, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरूरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, नगर मजिस्ट्रेट प्रशान्त तिवारी तथा जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार सहित सभी उप जिलाधिकारी, जिलास्तरीय अधिकारी तथा भारी संख्या में लाभार्थी आदि उपस्थित रहें।

किसानों का धान पूरी निष्पक्षता एवं ईमानदारी से क्रय किया जाये :- मण्डलायुक्त

क्रय केन्द्रों पर किसानों को सभी सुविधायें उपलब्ध करायें:- डा0 रोशन जैकब

'रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' मण्डलायुक्त डा0 रोशन जैकब ने गुरुवार को शाहाबाद गल्ला मंडी में सरकारी धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मण्डलायुक्त ने केन्द्र प्रभारियों से धान खरीद, बोरा एवं अन्य वारदाना के बारे में जानकारी ली तथा निर्देश दिये कि धान केन्द्र क्रय पर आने वाले किसानों का ध ान पूरी निष्पक्षता एवं ईमानदारी से क्रय किया जाये और किसानों को सभी सुविधायें उपलब्ध करायें।

उन्होने कहा कि किसानों का ध ान नियमानुसार नमी की जांच करें और उनका समय पर भुगतान भी करायें और 60 कुन्तल तक ध ान लाने वाले किसानों का धान प्राथमिकता के आधार पर क्रय किया जाये। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार तथा खाद्य एवं विपणन अधिकारी उपस्थित रही।

तेज तर्रार एसआई स्नेहा राय को सिपाह पुलिस चौकी की कमान

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। पुलिस अधीक्षक डा. अजय पाल शर्मा ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है, महिलाओं पर हो रहे अपराध को रोकने की सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मद्देनजर तेज तर्रार महिला एसआई स्नेहा राय को शहर कोतवाली की सिपाह पुलिस चौकी की कमान सौंपी गई है ।

इसके पहले स्नेहा राय जफराबाद थाने पर तैनात रहीं , माना जा रहा है कि तेज तर्रार व अच्छी छवि के कारण ही इन्हें सिपाह पुलिस चौकी का प्रभारी बनाया गया है ,सिपाह चौकी के प्रभारी अरविंद कुमार यादव टीडी कालेज चौकी का प्रभारी बनाया गया है ।

आशुतोष गुप्ता को टीडी कालेज से चौकियां पुलिस चौकी का चार्ज दिया गया है। सुनील यादव को पुरानी बाजार चौकी की जिम्मेदारी दी गई है ।

करवा चौथ के दिन माता पिता को फावड़े से काट कर मौत के घाट उतारा

अयोध्या (क्राइम रिपोर्टर) मुकेश कुमार। अयोध्या हैरिगटनगंज पुलिस चौकी अंतर्गत सागर पट्टी पंधिला निवासी बालेंद्र ने फावड़े से अपने मां बाप की काटकर की हत्या। रात में शराब पीकर आया आरोपी अपनी पत्नी को पीट रहा था जिसका उसके मां–बाप ने विरोध किया जिससे नाराज होकर बालेंद्र मारने की धमकी देकर कहीं चला गया। रात लगभग 11 बजे जब लौटा तो पड़ोसी के द्वार पर रखे फावड़े से बिस्तर पर लेटे अपने पिता राज मणि उर्फ मनी तिवारी उम्र लगभग 62 वर्ष पर हमला कर दिया जब मां ने गुहार लगाई तो मां को भी काट डाला। आरोपी शायद पुलिस चौकी हैरिंग्टनगंज के पास पान की दुकान लगाता है और 2 भाइयों में बड़ा है।

राम मंदिर में पूजे जाएंगे 100 क्विंटल चावल, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दिया ऑर्डर

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो) सुरेंद्र कुमार।अयोध्या रामनगरी में राम मंदिर में पूजे गए चावल को रंगने के बाद इसे पीतल के कलश में रखा जाएगा, जिसे 5 नवंबर को पूजा के दौरान भगवान राम के दरबार के सामने रखा जाएगा, फिर चावल को विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से वितरित किया जाएगा,इसके अलावा राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में दो करोड़ से अधिक पर्चे भी छपवाये गये हैं,इन्हें चावल के साथ देश के हर घर में भेजा जाएगा।

अयोध्या के दीपोत्सव में वैश्विक पहचान दिलाई: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो) सुरेंद्र कुमार।अयोध्या डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं प्रदेश राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या के प्रान्तीयकृत दीपोत्सव में सहभागिता के लिए राजभवन में कुलपति प्रो0 प्रतिभा गोयल को राम की पैड़ी पर दीयों को उनकी ओर से प्रज्ज्वलित करने की सामग्री सौपी। अवध विवि प्रशासन राज्यपाल द्वारा दी गई दीपों की सामग्री दीपोत्सव की सहभागिता में शामिल होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के प्रान्तीयकृत दीपोत्सव को एक वैश्विक पहचान दिलाई है। विश्वभर की निगाहें अयोध्या दीपोत्सव पर लगी रहती है। इसमें आमजन की सहभागिता हो सके इसके लिए प्रतीकात्मक रूप से 100 से 400 मिलीग्राम तक सरसों तेल, बाती व मोमबत्ती के एक पैकेट का जनसहयोग 31 अक्टूबर तक चलाया गया। कुलपति प्रो0 गोयल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुरूप 11 नवम्बर को होने वाले सातवें दीपोत्सव की तैयारियां विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगभग पूरी की जा चुकी है। 21 लाख दीए प्रज्ज्वलित करने के लिए स्वयंसेवकों में उत्साह देखते ही बन रहा है। सातवें दीपोत्सव में छठी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज करेंगे। विवि दीपोत्सव नोडल अधिकारी प्रो0 संत शरण मिश्र ने बताया कि कुलपति के निर्देश पर दीपोत्सव की तैयारियां तेजी के साथ की जा रही है। 50 प्रतिशत से अधिक वालंटियर्स कार्ड वितरित कर दिया गया है। 05 नवम्बर से वालंटियर्स के लिए टी–शर्ट व कैप विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, महाविद्यालयों, इण्टर कालेजों व स्वयंसवी संस्थाओं को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

निराश्रित गौवंश संरक्षण अभियान का हुआ शुभारंभ

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो) सुरेंद्र कुमार।नोडल अधिकारी प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ आनंद कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर नगर निगम के वाहनो को किया रवाना, सर्किट हाउस से किया रवाना, जनपद में घूम रहे गोवंशों को पकड़ कर लाया जाएगा गौ आश्रय, गौ आश्रयो को भी किया जाएगा विस्तारित, 1 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर तक 60 दिनों तक का चलेगा विशेष अभियान, तहसील व ब्लॉक स्तर पर नामित नोडल अधिकारी गोवंशों को पकड़ने के लिए टीम का करेंगे गठन, हॉटस्पॉट होंगे चिन्हित, जहां पर ज्यादा गौवंश होते हैं इकट्ठा उन स्थानों को किया जाएगा चिन्हित।

एक शाम अयोध्या जी के नाम आगामी 4 नवंबर को अयोध्या धाम चौरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित

अयोध्या (काइम रिपोर्टर) मुकेश कुमार। इस कार्यक्रम में 2100 दीप प्रज्वलित करके डांडिया व गरबा का सांस्कृतिक कार्यक्रम शहर के नियर नाका बाईपास स्थित के टी पब्लिक स्कूल में आयोजित होगा, उपरोक्त कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अयोध्या धाम चौरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय महिंद्रा ने बताया की कार्यक्रम का शुभारंभ 2100 दीप प्रज्वलित तथा कार्यक्रम में डांडिया गरबा का संस्कृत कार्यक्रम आयोजित होगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश होंगे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नेत्र सर्जन डॉ संजीव थापर डॉ जावेद अख्तर डॉ सीताराम अग्रवाल पूर्व प्राचार्य प्रीतम सिंह व्यापारी नेता सुशील जायसवाल सर्राफा मंडल के नरेश अग्रवाल अतिथि के रूप में महिला थाना अध्यक्ष निशा शुक्ला डॉ स्वदेश मल्होत्रा डॉ आशुतोष प्रताप सिंह डॉक्टर गरिमा सिंह डॉ प्रियंका त्रिपाठी होंगे कार्यक्रम में बेस्ट कपल बेस्ट डांस बेस्ट ड्रेस बेस्ट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को चमचमाती हुई मोमेंट सहित चांदी का पायल आदि उपहार दिया जाएगा श्री महिंद्रा ने बताया कि डांडिया व गरबा कार्यक्रम में कोई भी ग्रुप तथा महिला पुरुष कपल हिस्सा ले सकता है जिनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है स्कूल के 40000 स्क्वायर फीट से ज्यादा के मैदान में दूधिया लाइट रंगीन फॉक्स लाइट नए लाइटों के संसाधन व साउंड के तहत शहर का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभा होटल के सभागार में ट्रस्ट व आयोजन समिति की एक बैठक आयोजित की गई जिस बैठक को मुख्य रूप से संबोधित करने वालों में साकेत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सीताराम अग्रवाल डॉक्टर जावेद अख्तर प्रीतम सिंह श्रीमती पूनम सिंह डीएन वर्मा सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक श्रीमती बबीता पूर्ण रंगमंच के कलाकार पीके गौर ट्रस्ट के महामंत्री प्रतीक वैश्य भज्जा कोषाध्यक्ष एकता टंडन उपाध्यक्ष भारती सिंह एडवोकेट नीलम श्रीवास्तव सचिन सरीन मंजूर खान अवधेश कुमार शुक्ला कविंद्र साहनी सांस्कृतिक प्रभारी राजन कुमार अरोड़ा प्रशांत केसरवानी सचि व संजय सरीन श्रीमती सुचिता भल्ला श्रीमती बबीता यादव पूनम शर्मा श्रीमती आरती शुक्ला श्रीमती मीना अवस्थी गुड़िया मौर्य रेखा विश्वकर्मा उमेश चंद्र इंजीनियर विनोद कुमार शर्मा कंचन राठौर मुख्य रूप से उपस्थित थे।

छात्रों को यातायात के नियमों की जानकारी दें : इंस्पेक्टर विद्यासागर पाल

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

सकरौली, हरदोई। थाना पचदेवरा प्रभारी निरीक्षक विद्यासागर पाल के नेतृत्व में यातायात माह नवंबर 2023 के शुभारंभ के अवसर पर आज दिनांक 1/11/2023 को अनंगपुर चौराहे पर चालकों व नागरिकों को एकत्रित कर यातायात नियमों के संबंध में सभी को भलीभांति अवगत कराते हुए जागरूक किया गया एवं नियमों का पालन किए जाने के लिए अनुरोध किया गया एवं यातायात नियमों को पालन करने का संकल्प लिया गया।

यातायात माह नवंबर 2023 के क्रम में यातायात जागरूकता रैली निकली गई। इसमें काफी संख्या में चालक व आम नागरिको द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, होमगार्ड के जवान एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। इंस्पेक्टर विद्यासागर पाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नवंबर माह लोगों को यातायात के नियमों की शिक्षा देने के लिए होता है इसलिए सभी चौकी इंचार्ज अपने–अपने क्षेत्र के कॉलेज में जाकर छात्रों को यातायात के नियमों की बेसिक जानकारी दें। उन्होंने कालेज के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्य को सहयोग करने की अपील की। उप निरीक्षक कॉलेज असेंबली के समय जाकर यातायात के नियमों की थोड़े समय में ही बेसिक जानकारी दे सकते हैं।

राजधानी की यातायात व्यवस्था एवं जाम से बचने के उपायों पर की चर्चा

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। लखनऊ की यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु वाणिज्य बंधु की बैठक में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी को दिए सुझाव लखनऊ में रात्रि बाजार शुरू करने, शहर में मेट्रो रूट बढ़ाने एवं सार्वजनिक परिवहन के वाहनों की संख्या बढ़ाने एवं अनिवार्य रूप से वर्तमान में नये बन रहे भवनो में पार्किंग के अनिवार्य निर्माण बनाए जाने का सुझाव दिया। नगर निगम द्वारा जी आई एस सर्वे से व्यापारियो को गलत हाउस टैक्स बिल भेजे जाने का विषय भी बैठक में उठाया पत्रकार पुरम में पेट्रोल पंप के बगल में पार्किंग वाली सड़क पर वेंडिंग जोन को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने एवं खजाना मार्केट आशियाना के पास बने वेडिंग जोन को भी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की भी मांग उठी 2 नवंबर, बृहस्पतिवार जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में वाणिज्य बंधु की बैठक जिलाधिकारी महोदय श्री सूर्यपाल गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में राजधानी की यातायात व्यवस्था एवं जाम से बचने के उपायों पर चर्चा भी की गई उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बैठक में राजधानी में रात्रि बाजार शुरू किए जाने ,शहर में मेट्रो रूट की लाइन बढ़ाने, सार्वजनिक परिवहन के वाहनों की संख्या बढ़ाने तथा वर्तमान में नए बन रहे भवनो में अनिवार्य रूप से पार्किंग निर्माण के सुझाव दिए तथा ई रिक्शा पर भी अंकुश लगाने का विषय बैठक में उठा व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने नगर निगम द्वारा व्यापारियों को जी एस आई सर्वे के नाम पर गलत हाउस टैक्स बिल भेजे जाने की भी शिकायत की

बैठक में पत्रकारपुरम पार्किंग के सामने वाली सड़क में बनाए गए वेडिंग जोन को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने तथा आशियाना खजाना मार्केट के वेडिंग जोन को भी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का विषय उठा बैठक में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ,प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद अफजल ,ट्रांस गोमती अध्यक्ष अनिरुद्ध निगम एवं राजधानी के अन्य व्यापारी संगठनो के पदाधिकारी मौजूद रहे।

कांग्रेस नेता मोहसिना किदवई के भतीजे का अश्लील वीडियो

कांग्रेस नेता बोले, वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही

एजेन्सी

लखनऊ। कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता मोहसिना किदवई के भतीजे और कांग्रेस पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष महबूब उर रहमान किदवई के अश्लील वीडियो सामने आए हैं। अलग–अलग महिलाओं के साथ वीडियो सामने आने के बाद महबूब उर रहमान किदवई पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं महबूब उर रहमान किदवई की इस काली करतूत के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस का कोई भी नेता इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता रहमान किदवई का कहना है, ये उनको फंसाने की साजिश है। जिस महिला ने ये वीडियो वायरल किए हैं, वो उनसे मोटी रकम की मांग करती रही है। वो उसको लगभग 2 साल से हर महीने 50 हजार रुपए देते आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों से उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया था। वो उनसे अब 50 लाख रुपए हर महीने मांग रही है, नहीं देने पर उसने ये वीडियो वायरल किए हैं। रहमान किदवई ने महिला के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में शिकायती पत्र दिया है। बताया जा रहा है, कांग्रेसी नेता रहमान किदवई लंबे समय से लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में रह रहे थे। वो बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के रहने वाले हैं। महिला भी गोमती नगर इलाके की ही रहने वाली बताई जा रही है। कांग्रेस नेता रहमान किदवई का आरोप है, कोरोना के समय पर वो उस महिला के संपर्क में आए थे। उसके बाद से ही उनकी महिला से जान पहचान हुई थी।

दीपावली के त्यौहार को देखते हुए बाजारों में पुलिस गस्त अतिरिक्त कराई जाए: व्यापारी नेता अमरनाथ मिश्र

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। वाणिज्य वंधु की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अब्दुल कलाम सभागार कलेक्ट्रेट लखनऊ में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से अमरनाथ मिश्र पवन मनोचा विनोद अग्रवाल अनुराग मिश्र उमेश शर्मा देवेंद्र गुप्ता सुहैल हैदर अल्वी जितेन्द्र सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे।

लखनऊ व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे अध्यक्ष श्री मिश्र ने बताया कि जीएसटी लागू होने के डेढ़ साल तक पोर्टल पर प्रयोग होते रहे। ळैज्–2ठ एवं वार्षिक रिटर्न समय से लागू नहीं हो पाये जिससे सरकार स्वयं समय सीमा बढ़ती रही. जिससे वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में गलतियां होती रही है।

विचारणीय बिंदु यह है कि क्रेता व्यापारी द्वारा एक्टिव फॉर्म देखकर माल खरीदा गया और ट्रांसपोर्ट भाड़े पर आरसीएम एवं एक्ट के अनुसार ई वेबिल भी जनरेट किया गया उक्त खरीद इनवॉइस का पेमेंट बैंक के माध्यम से किया। इन सभी बिंदुओं का पालन करने के बाद व्यापारी की जिम्मेदारी क्यों ?

टैक्स चोरी करने के लिए बनी बोगस फॉर्म का पंजीकरण ळैज् विभाग द्वारा दिया गया है।

जीएसटी विभाग द्वारा धारा 74 के तहत टैक्स (आईटीसी) एवं ब्याज सहित पेनल्टी जमा करने की नोटिस जारी की है। जो फार्म बोगस ना होकर एक्टिव है कर निर्धारण अधिकारी विक्रेता से प्रश्न क्यों नहीं पूछता है कि आपके द्वारा कर संग्रह कर सरकार को क्यों नहीं जमा कराया गया जिसकी नोटिस भेजी जानी चाहिये।ऐसा होने पर सरकार का तमाम टैक्स जमा हो जाएगा यहां पर यहां भी महत्वपूर्ण बिंदु है की धारा 16 सी को ध्यान में रखकर जीएसटी में एक्टिव फार्म और न जमा करने वाली फॉर्म को जिम्मेदार न मानकर कर अदा कर आईटीसी लेने वाले इमानदार व्यापारी से वसूली की जा जा रही है जो की एक्ट की बहुत बड़ी खामी उजागर करता है सैद्धांतिक रूप से सरकार टैक्स को संग्रह कर जमा न करने वाला दोषी हो ना की टैक्स को अदा कर आईटीसी लेने वाला । 2017–18 के सीएसआर 9 में टेबल 8 पार्टी वाइज लिस्ट डाउनलोड नहीं होती थी जिसे या नहीं मालूम हो पाया कैसे पार्टी को आईटीसी नहीं आई है जारी नोटिस का जवाब देने हेतु समय सीमा बढ़ाई जाए क्योंकि त्यौहार का सीजन चल रहा है और विक्रेता व्यापारी से टैक्स संग्रह का स्टेटमेंट लेने में देरी हो रही है अतः सभी नोटिस की तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 की जाए

यातायात पुलिस

दीपावली के त्यौहार को देखते हुए बाजारों में पुलिस गस्त अतिरिक्त कराई जाए।

व्यवस्थम चौराहे पर सुबह 9रू00 बजे से रात्रि 9रू00 बजे तक पुलिस तैनात की जाए।

जाम की स्थिति को खत्म किया जाए।

नगर निगम

यहियागंज कंघी वाली गली में नाली चौक होने के कारण जल भराव की समस्या बनी हुई है डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी अपने पैर पसारे है उसके बावजूद नगर निगम जॉन जॉन नहीं पाया है जल भराव से व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अतः इसे तत्काल सही कराया जाए।

सशक्त, समर्थ,स्वाबलंबी भारत के निर्माण के लिए महिलाओं के कल्याण की योजनाएं दीं : योगी आदित्यनाथ

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना)। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन उधरनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने आधी आबादी को ध्यान में रखकर हर योजना बनाई है। सशक्त, समर्थ,स्वाबलंबी भारत के निर्माण के लिए महिलाओं के कल्याण की योजनाएं दीं।

नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में सीएम ने 541 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण,शिलान्यास उद्घाटन कर, उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जनधन संग्रह योजना, उज्जवला योजना,हर घर नल योजना,घर घर शौचालय योजना,आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना,घर घर बिजली कनेक्शन योजना एवं दो करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की योजनाओं से महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।आज बहनें ट्रेन,बस, फाइटर जेट से लेकर राफेल तक चलाने का कार्य कर रही हैं। चन्द्रयान मिशन से लेकर एशियन गेम्स में महिलाओं का उत्कृष्ट योगदान है।

प्रधानमन्त्री ने 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं को सदन तक भेजने का मार्ग सशक्त किया।

योगी जी ने बताया कि महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम से सदन की एक तिहाई सीटों पर शोभायमान होने का मौका मिलेगा।

कहा कि गरीब,जरूरतमंद महिलाओं प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 04 करोड़ महिलाओं को मकान मिले।हरदोई जिले एक लाख 12 हजार परिवारों को आवास दिए।उनका आरोप था कि पहले दबंग गरीबों की झोपड़ी हटा देते थे।पहली बार स्वामित्व योजना के अंतर्गत गरीब को झोपड़ी वाले स्थान पर मालिकाना हक मिलेगा एक करोड़ 25 लाख परिवारों को स्वामित्व दिया।पीएम स्व निधि योजना अंतर्गत बैंकों के माध्यम से पटरी दुकानदारों व्यवसाईयों को ब्याज मुक्त ऋण देकर लाभान्वित किया।करीब 14 लाख पटरी व्यवसाई लाभान्वित हुए। इन व्यवसाईयों में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। परिवार स्वावलंबन सुरक्षा की दृष्टि से शोषण मुक्त समाज बनाया। बेटियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए 1947 से लेकर 2017 तक 70 वर्षों तक केवल 10000 महिलाएं कार्मिक थी उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती करके 40000 महिला पुलिस कार्मिक तैनात की।हर भर्ती में 30 फीसदी महिलाएं शामिल हैं। एशियन गेम्स में पीएम खेल योजना, खेलो इंडिया खेलो योजना, फिट इंडिया मूवमेंट एवं एशियन गेम्स में 111 मेडल खिलाड़ियों ने प्राप्त किया। राज्य सरकार ने तय किया कि एशियाई गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में सफल रहने वाले खिलाड़ियों को शासन की विभिन्न सेवा योजनाओ में समायोजित किया जाएगा। गेम्स विजेता बेटियों को सेवाओं का मौका देंगे।

आज सरकार बेसिक शिक्षा परिषद में बेटियों को बुक्स ड्रेस शूज स्वेटर आदि मुफ्त में दे रही है। प्रदेश में एक करोड़ 95 लाख बच्चों को डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। कन्या सुमंगला योजना स्नातक तक पढ़ाई के लिए 15000 की राशि सालाना देने का काम सरकार ने किया। आगे से सरकार बेटियों को शिक्षा के लिए25000 सालाना देगी। इस योजना से 17000 बेटियां लाभान्वित हुई। अब बेटियों की शादी के लिए अभिभावक को कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 3 लाख बेटियों की शादी हो चुकी है जिन्हें 51ऋ 51 हजार रुपए दिया गया 29 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को 12 हजार रुपए सालाना पेंशन दी जा रही है।

नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी, पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल, राज्यसभा सांसद अशोक बाजपेई ,जनपद हरदोई के प्रभारी मंत्री जीपीएस राठौर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल सांसद जयप्रकाश रावत ,अशोक रावत विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रामपाल वर्मा, श्याम प्रकाश प्रभास कुमार आशीष सिंह आशु ,अलका अर्कवंशी, एमएलसी अशोक अग्रवाल अवनीश कुमार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, जिला महामंत्री सत्येंद्र कुमार सिंह राजपूत, अनुराग मिश्रा भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अलका गुप्ता सहित हजारों की संख्या में महिलाएं और ग्रामीण जन शामिल हुए।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया।

स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे की बैठक संपन्न

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में डायट की स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे की बैठक बुधवार देर सायं संपन्न हुई।

बैठक में कक्षा 3, 6 एवं 9 के विद्यार्थियों के उपलब्धि आकलन हेतु 03 नवंबर 2023 को State Educational Achievement Survey 2023 (SEAS) के आयोजन के संबंध में चर्चा हुई । यह उपलब्धि सर्वेक्षण जनपद के सैम्पल्ड विद्यालयों मे कराया जाना है। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत भाषा एवं गणित विषयों में आकलन किया जाना है। इस कार्य हेतु प्रत्येक सैम्पल्ड विद्यालयों में फील्ड इन्वेस्टीगेटर (FI) तैनात किये गये है। यह आकलन सर्वे 03 नवम्बर 2023 को पूर्वान्ह 9रू00 बजे से आरम्भ होगा, प्रत्येक विकास खण्ड में ब्लाक लेबल कोआर्डिनेटर BLC (BEO/ARP) को तैनात किया गया है। सर्वेक्षण समाप्ति के उपरान्त सम्बंधित पैकेट ठम्द्व द्वारा बनाये गये ब्लाक स्तरीय कन्ट्रोल रूम में फील्ड इन्वेस्टीगेटर (FI) द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्यध्प्रधानाध्यापक के सहयोग से जमा कराया जायेगा तथा ब्लाक लेवल कोआर्डिनेटर BLC द्वारा सम्बंधित पैकेट जिला मुख्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर (डायट) में बनाये गये कन्ट्रोल रूम में जमा कराया जायेगा। State Educational Achievement Survey 2023 (SEAS) में जनपद के जनपदीय, तहसील स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों की जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती की जानी है। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि. एवं रा. राम अक्षयबर चौहान, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित अन्य उपस्थित रहे।

सुल्तानपुर के बीजेपी विधायक की लापता पत्नी बाराबंकी में मिली

एजेन्सी

लखनऊ। सुल्तानपुर के लंभुआ से भाजपा विधायक सीताराम वर्मा की पत्नी मंगलवार सुबह घर से अचानक गायब हो गईं। विधायक के बेटे ने गाजीपुर थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में लगी। बुधवार दोपहर को विधायक की पत्नी बाराबंकी के सफेदाबाग में मिली। वो भटकते हुए वहां पहुंच गईं थीं। बता दें कि विधायक सीताराम वर्मा का गाजीपुर सेक्टर–8 में घर है।

हिन्दी सांध्य दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित ।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0–7007415808,9628325542,9415034002

RNI संन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R-1

deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायलय होगा।